# राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, झारखण्ड
# संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
# दिनांक : 15.02.2021
# स्थान- नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

## राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 74 वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत

## Minutes of the 74th Quarterly Meeting of SLBC, Jharkhand

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 74वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय सभागार, रांची से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दिनांक 15.02.2021 को किया गया। इस बैठक में वित्तीय सेवाए विभाग, भारत सरकार के संयुक्त सचिव डॉ॰ मदनेश कुमार मिश्रा, विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार श्री के॰ के॰ खंडेलवाल, रिजर्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबन्धक श्री संजीव दयाल, नाबार्ड राँची क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबन्धक श्रीमती एन्नी एलेक्सजेंडर, एसएलबीसी, झारखंड के महाप्रबंधक श्री राजेंद्र मान पाण्डेय, विशेष सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार श्रीमती दीप्ती जयराज, एसएलबीसी, झारखंड के उप-महाप्रबंधक श्री गणेश टोप्पो एवं भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबन्धक श्री राजेश रंजन तिवारी नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के सभागार मे उंपस्थित थे | इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक के उपमहाप्रबंधक श्री अनाथबंधू मंडल एवं सहायक महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के महाप्रबंधक श्री अनिल कुरिल एवं केनरा बैक के महाप्रबंधक श्री हितेश गोयल भी क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड सभागार में उपस्थित थे | साथ-ही-राज्य सरकार से श्रीमती हिमानी पाण्डेय वित्त सचिव, श्रीमती आराधना पटनायक, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं श्री अबूबक्कर सिद्दीक, सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुये | इनके अतिरिक्त, PFRDA के सीजीएम, सभी बैंको के राज्य नियंत्रक, सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं राज्य सरकार के अन्य विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक मे जुड़े थे |

बैठक की शुरुआत में सभागार में उपस्थित गणमान्य विशेष सदस्यों को पुष्प गुच्छ एवं पुस्तक भेंट कर किया गया। त्रैमासिक बैठक में मंच का संचालन श्री बिभव कुमार के द्वारा किया गया। श्री कुमार ने उपरोक्त बैठक को प्रारम्भ करने हेतु SLBC, महाप्रबंधक श्री राजेंद्र मान पाण्डेय को संबोधन के लिए आमंत्रित किया |

महाप्रबंधक, SLBC-झारखंड, श्री राजेंद्र मान पाण्डेय ने सर्वप्रथम सभा में उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों एवं विडियो कांफ्रेन्सिंग से जुड़े सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया, तत्पश्चात सभा को संबोधित करते हुए बताया कि कोरोना काल में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की चौथी समीक्षा बैठक विडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है | श्री पाण्डेय ने अपने सम्बोधन मे निम्न विषयों पर सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया :-

वित्तीय समावेशन की दिशा में PFRDA द्वारा SLBC झारखण्ड को H1, 2020-21 (Sep-Oct,20) के लिए Award of Execellance प्रदान करने हेतु आभार प्रकट किया | साथ ही साथ दो बैंकों JRGB एवं सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया तथा LDM पाकुड़ एवं गुमला को भी Certificate of Execellence प्राप्त करने हेतु बधाई दिया |

सामाजिक सुरक्षा की अन्य महत्वकांक्षी योजनाएं, सुरक्षा एवं जीवन ज्योति बीमा योजना की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में राज्य मे अभी भी काफी कार्य किया जाना शेष है | उन्होंने DFS द्वारा प्रायोजित Targeted Financial Inclusion Intervention Programme के तहत राज्य के 19 आकांक्षी जिलों में सितम्बर ,21 तक विभिन्न परिमापों मे शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सभी सदस्यों द्वारा निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया |

**(एक्शन-समस्त बैंक, एलडीएम,राज्य सरकार)**

श्री पाण्डेय ने आगे कहा कि वार्षिक ऋण योजना (ACP) 2020-21 के अंतर्गत दिसम्बर तिमाही तक कुल ऋण की उपलब्धि 75% के करीब है, किन्तु कृषि क्षेत्र में केवल 31% की उपलब्धि निश्चित ही विचारनीय है | इस सम्बन्ध में विशेषकर एलडीएम तथा डीडीएम नाबार्ड को District Credit Plan की समीक्षा करनी चाहिए एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु District Credit Plan को Realistic बनाने आवश्यकता है | झारखण्ड राज्य के गठन के बाद से अभी तक कृषि क्षेत्र की प्रगति देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी दयनीय है , हालाँकि राज्य में कृषि मे सम्बंधित काफी संभावनाएं है, विशेषकर Micro Irrigation, Integrated Farming, Agri Infra, Solar Power की दिशा में काफी कुछ किया जा सकता है | इस सम्बब्ध में सभी हितधारकों को सुनियोजित कार्ययोजना के तहत कार्य करने की आवश्यकता है |

**(एक्शन-समस्त बैंक, एलडीएम,नाबार्ड राज्य सरकार)**

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकज के अंतर्गत विभिन्न योजनाएँ बैंकों के माध्यम मे चलायी जा रही है, जिसमें विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत राज्य के सभी बैंकों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिससे कोविड महामारी के कारण आर्थिक मंदी से जूझ रहे देश की अर्थव्यवस्था, अब धीरे-धीरे रफ़्तार पकड़ रही है | झारखण्ड में इस योजना के तहत बैंकों के द्वारा ECLGS, KCC Saturation Drive under Dairy-Fisheries Activities एवं PM Kisan Beneficiaries, CGSSD एवं PM SVANidhi योजनायों में ऋण वितरित किये जा रहे हैं |

हालाँकि, कोरोना काल में राज्य का ऋण-जमा अनुपात विशेषत: सितम्बर तिमाही में काफी गिरावट दर्ज की गई थी एवं दिसम्बर तिमाही में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है | ECLGS योजना के अतर्गत राज्य के सभी बैंकों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है | इस योजना में कुल Eligible खातों की संख्या 1.18 लाख तथा कुल रु. 1906.32 करोड़ ऋण वितरण के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 2020 तिमाही तक बैंकों द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 93.81% ऋण स्वीकृति एवं 88.40% ऋण वितरण किया जा चुका है |

**(एक्शन-समस्त बैंक, एलडीएम)**

इसी क्रम में उन्होंने आगे कहा कि शहरों में ठेले वाले, सब्जी वाले, गरीब रेहड़ी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) को कोरोना महामारी के दौरान PM SVANidhi योजना के तहत बैंकों के माध्यम के रु. 10,000/- का ऋण दिया जा रहा है | इस योजना में, झारखण्ड राज्य में 75,000 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण देने का लक्ष्य MoHUA, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें जनवरी, 2021 तक कुल 33,082 स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदन PM स्वनिधि पोर्टल पर अपलोड किये गए हैं | इनमें से 16,302 ऋण आवेदन स्वीकृत एवं 13,601 ऋण आवेदन वितरित किये जा चुके हैं | उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि इसमें और अधिक तेजी लाने की जरुरत है | साथ ही साथ उन्होंने राज्य सरकार के सम्बंधित विभाग से भी अनुरोध किया कि स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों तक जोड़ने में व्यापक पहल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके |

**(एक्शन-समस्त बैंक, एलडीएम, नगरिय विकास विभाग,राज्य सरकार)**

KCC Saturation Drive के अंर्तगत राज्य के डेयरी एवं फिशरी एक्टिविटी से जुड़ें किसानों को भी KCC योजना से जोड़ने के लिए झारखण्ड राज्य मिल्क फेडरेशन, डेयरी डेवलपमेंट एवं फिशरी विभाग से आवेदन सृजित कर बैंकों में भेजे जा रहें | बैंकों द्वारा जनवरी, 2021 तक डेयरी क्षेत्र में 4749 एवं फिशेरी में 1264 ऋण आवेदन Sanction किया गया है | हालाँकि, अभी भी लंबित आवेदनों की संख्या एक चिंतनीय आंकड़ा है | बैंक शाखाओं को प्राप्त आवेदन एवं राज्य सरकार के डेयरी एवं फिशरी विभाग द्वारा प्रेषित आवेदनों की संख्या में विसंगतियों बैंकों द्वारा बताई गई | इस सम्बन्ध में बैंकों एवं सम्बंधित विभागों से अनुरोध किया गया कि वे त्वरित रूप में आवेदनों का मिलान कर निस्तरण करें |

**(एक्शन-समस्त बैंक, एलडीएम, नाबार्ड)**

राज्य में NPA, विशेषकर Government Sponsored Cases में काफी ज्यादा NPA होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बैंकों की राज्य सरकार से अपेक्षा है कि शेष 17 जिलों में सर्टिफिकेट ऑफिसर की नियुक्ति अविलम्ब की जाये, ताकि बैंक अपने NPA की वसूली कर सकें | उन्होंने बताया कि Physical Possession से सम्बंधित 284 Cases विभिन्न बैंकों द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किये गए हैं, राज्य सरकार से अपेक्षा है कि सम्बंधित जिलों के उपायुक्तों को इन सभी लंबित मामलों के समाधान हेतु बैंकों को सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करें |

**(एक्शन-समस्त बैंक, एलडीएम,राज्य सरकार)**

एसएलबीसी महाप्रबंधक ने बताया कि दिसम्बर, 2020 तिमाही में SHG Finance में कुछ बैंकों जैसे :- IDBI, PNB एवं SBI में उच्च स्तर NPA क्रमशः 73.71%, 54.67% एवं 19.84% है, जो कि काफी चिंता का विषय है | उन्होंने JSLPS से अनुरोध किया कि वे इस मामले का संज्ञान लें तथा समय से ऋण वापसी हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों के बीच निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलायें | इसी प्रकार उन्होंने PMEGP योजना के मामले में भी बैंक ऑफ़ बरोदा, बैंक ऑफ़ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, इंडियन बैंक, झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक, PNB, SBI, UCO बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया का एनपीए प्रतिशत 25% से अधिक होने पर चिंता जतायी |

**(एक्शन-समस्त बैंक, एलडीएम,JSLPS,KVIC)**

अंत मे उन्होंने बताया कि राज्य में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) के तहत 31.12.2020 तक विभिन्न बैंकों द्वारा अबतक कुल 1.53 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिसमें 83.04% खातों में आधार सीडिंग एवं 73.62% खातों में मोबाइल सीडिंग किया जा चुका है | इसके अतिरिक्त 70.88% खातों में रूपे कार्ड जारी किया गया है, हालाँकि इनमें से केवल 58.28% खातों में ही रूपे कार्ड एक्टिव किये जा सके हैं |

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत PFRDA द्वारा राज्य को वर्ष 2020-21 हेतु कुल 1.66 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर,2020 तिमाही तक कुल 1.75 लाख नए लोगों को जोड़ा गया है, जो तय लक्ष्य से अधिक है| इसके लिए सभी बैंक बधाई के पात्र हैं | सभी बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अपना योगदान देते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करेंगें |

इस सम्बोधन के पश्चात नाबार्ड के महाप्रबंधक श्रीमती एन्नी अलेक्स्जेंडर को सभा को संबोधित करने का आग्रह किया गया। श्रीमती एन्नी अलेक्स्जेंडर ने निम्न विषयों पर परिचर्चा की:-

महाप्रबंधक नाबार्ड ने बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए राज्य स्तर पर PLP (Potential Link Credit Plan) तैयार किया जा चुका है, जिसमें अगले वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता क्षेत्र हेतु रु. 24,643 करोड़ एवं कृषि क्षेत्र के लिए रु. 11,183 करोड़ क्रेडिट की वृद्धि का अनुमान तय किया गया है | उन्होंने सभी LDMs से अनुरोध किया कि जिला स्तर पर PLP जारी किया जा चूका है, सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों के द्वारा शाखा स्तर पर DCP तैयार करते हुए DCC की बैठक के द्वारा अनुमोदित कर SLBC एवं नाबार्ड को प्रेषित करें, जिससे राज्य स्तर पर ACP 2021-22 का लक्ष्य निर्धारित किया जा सके |

**(एक्शन- एलडीएम,डीडीएम-नाबार्ड)**

श्रीमती अलेक्स्जेंडर ने बताया कि राज्य के लघु सिंचाई फण्ड में वृद्धि कर रु. 10,000 करोड़ की गई है, जो कि गत वर्ष केवल रु. 5,000 करोड़ था | इससे राज्य में सिंचित भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी | राज्य में अभी भी काफी भूमि असिंचित है एवं कृषि कार्य मानसून पर निर्भर रहती है | उन्होंने बताया कि इस वर्ष RIDF का रु. 10,000 करोड़ का फण्ड राज्य के विकास के लिए आबंटित किया गया है | इसमें से रु. 2,000 करोड़ का फण्ड कृषि योग्य भूमि को उपजाऊ बनाने पर खर्च किया जायेगा | उन्होंने आशा व्यक्त किया कि RIDF फण्ड राज्य के विकास के लिए काफी लाभकारी होगा | उन्होंने नाबार्ड द्वारा राज्य में चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की चर्चा की | उन्होंने कहा कि ये सभी प्रोजेक्ट्स राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-विकास में सहायक होगी, विशेषत: राज्य के 12 जिलें जहाँ RBI के अनुसार कम क्रेडिट flow है |उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष से एरिया डेवलपमेंट स्कीम की अवधि पांच वर्ष होगी तथा इसके लिए रु 1,500 करोड़ का फंड निर्धारित किया गया है | इसमें अभी डेयरी, फिशरी, बकरी-पालन, मुर्गीपालन समेत आठ एक्टिविटी को शामिल किया गया है | उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य में 35 वाटर शेड प्रोजेक्ट एवं 44 बाड़ी प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा |

**(एक्शन-समस्त सदस्य)**

उन्होंने JLG ( Joint Liability Group) के सम्बन्ध में बताया कि राज्य में JLG को प्रोमोट करने हेतु तीन बैंकों के साथ एग्रीमेंट किया गया है, जिसके अतर्गत प्रत्येक JLG के लिए रु. 4,000/- का ग्रांट दिया जायेगा | उन्होंने इसके लिए JSLPS को भी आगे आने का अनुरोध किया |

**(एक्शन- समस्त बैंक,जेएसएलपीएस)**

महाप्रबंधक नाबार्ड ने अंत में कहा कि एग्री इन्फ्रा फंड के अंतर्गत राज्य को रु. 1,445 करोड़ का लक्ष्य आगामी तीन वर्षों के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है | इस वर्ष इसके लिए रु. 145 करोड़ का लक्ष्य

दिया गया है, जिसे बैंक वार एवं जिलावार लक्ष्य सभी स्टेक होल्डर्स को आबंटित किया जा चूका है | हालांकि राज्य में एग्री इन्फ्रा फंड के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि शुन्य रही है | उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स से अनुरोध किया कि इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाये |उन्होंने राज्य में डेयरी एवं फिशरी किसानों को KCC प्रदान करने हेतु चलाये जा रहे KCC Saturation Drive की चर्चा करते हुए कहा कि अभी भी कुछ बैंकों में काफी आवेदन लंबित हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने की जरुरत है |

**(एक्शन- समस्त बैंक,एलडीएम,राज्य सरकार)**

इस सम्बोधन के पश्चात आरबीआई के महाप्रबंधक श्री संजीव दयाल को सभा को संबोधित करने का आग्रह किया गया। श्री दयाल ने निम्न विंदुओ को सदन के समक्ष पेश किया-

राज्य के CD ratio की चर्चा करते हुए लगातार गिर रहे सीडी रेशिओ के बारे मे श्री दयाल ने बताया कि पूर्व मे राज्य का सीडी रैशियो 60% था हालाँकि कि अभी यह लगभग 50% से थोड़ा ऊपर है | लॉकडाउन में छुट मिलने से इकोनोमिक गतिविधि दुबारा शुरू होने के कारण बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ में वृद्धि होनी चाहिए | इस कारण CD ratio में भी वृद्धि अपेक्षित है |

**(एक्शन- समस्त बैंक,एलडीएम)**

आरबीआई के महाप्रबंधक ने बताया कि दिसम्बर,2020 तिमाही के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि ऋण, MSMEs, Weaker Sections, Women एवं Minorities क्षेत्र में उपलब्धि मार्च, 2020 की तुलना में घटी है | इनमें एक से अधिक मामलों में यह SBI के द्वारा लगातार reporting घटाने के कारण पाया गया है | राज्य स्तर पर KCC के मामले में यह SBI द्वारा अचानक reporting घटाने के कारण कृषि क्षेत्र में भारी गिरावट आयी है | उन्होंने राज्य में अधिक शाखा परिचालन करने वाले बैंकों में एक SBI जैसे बड़े बैंक को reporting करने में अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरुरत है | इस सम्बन्ध में उन्होंने SLBC से अनुरोध किया कि वे RBI को बतायें कि क्या इस मुद्दे को SBI के LHO पटना को सूचित किया गया है और यदि ऐसा किया गया है, तो उनका इस विषय पर क्या मत है ?

**(एक्शन- भारतीय स्टेट बैंक)**

उन्होंने बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा कुछ जिलों में लंबित Financial Literacy Counsellor की नियुक्ति के मामले में कहा कि राज्य में बैंक ऑफ़ इंडिया के एकमात्र SLBC होने के नाते उनसे त्वरित कार्यवाई की आशा है |

**(एक्शन- बैंक ऑफ इंडिया)**

उन्होंने एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा झारखण्ड में उनके बैंकिंग आउटलेट से सम्बंधित जानकारी नहीं देने के सम्बन्ध में SLBC को सलाह दी कि इस मुद्दे को एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ के समक्ष उठाना चाहिए |

इसके साथ ही उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक एवं कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा SLBC को डाटा नहीं देने का कारण पूछा जाना चाहिए |

**(एक्शन- एसएलबीसी /एयरटेल पेमेंट बैंक/ आईसीआईसीआई बैंक/ कोटक महिंद्रा बैंक)**

श्री दयाल ने आगे कहा कि SLBC सब-कमेटी ऑन बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से राज्य के सभी गाँव जिनकी आबादी 2000 से कम है, 2000 से 5000 के बीच है या 5000 से अधिक है, ऐसे स्थानों में बैंकिंग आउटलेट को दुबारा अपडेट करने की जरुरत है | साथ ही साथ उन्होंने सलाह दी कि Financial Inclusion and Literacy पर SLBC की एक उच्च स्तरीय सब-कमेटी बनाने की जरुरत है | इस कमेटी में सभी बैंक, राज्य सरकार , NRLM, NULM, PMKVY etc से जुड़े प्रतिनिधियों को शामिल कर SLBC को इसकी बैठक यथाशीघ्र करनी चाहिए |

**(एक्शन- एसएलबीसी/ सभी बैंक, राज्य सरकार , NRLM, NULM, PMKVY etc )**

National Strategy of Financial Inclusion का मुख्य उद्देश्य Livelihood and Skill Development की पहुँच को गाँव तक पहुँचाना है | उन्होंने बैंकों में खाता खोलने वाले फॉर्म में ही सभी Skill Development, Livelihood Generation प्रोग्राम की जानकारी होनी चाहिए | इसके लिए सभी स्टेक होलेर्स का सहयोग अपेक्षित है |

**(एक्शन- एसएलबीसी/ सभी बैंक/ सभी एलडीएम/ राज्य सरकार/अन्य )**

श्री दयाल ने कहा कि इस वर्ष Financial Literacy Week (08 फ़रवरी से 12 फ़रवरी, 2021) का Theme Credit Discipline, Timely Repayment एवं Formalisation है | यह जानकर प्रसन्नता हुई कि Financial Literacy Week (08 फ़रवरी से 12 फ़रवरी, 2021) के इन पांच दिनों में पूरे राज्य में 250 से अधिक कैम्पों का आयोजन किया गया एवं बेसिक फाइनेंसियल literacy के संदेश को सभी प्रतिभागियों के साथ साझा किया गया | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता हेतु प्रथम फेज में राज्य के 263 प्रखंडों में से 132 प्रखण्ड में 44 CFLs की स्थपाना की मंजूरी दी गई है | ये सभी CFLs Swadhar FinAccess द्वारा संचालित किये जायेंगे तथा राज्य में इंडियन बैंक एवं बैंक ऑफ़ इंडिया स्पोंसर बैंक के रूप में कार्य करेंगे तथा सम्बंधित NGO के साथ तालमेल करते हुए इसे यथाशीघ्र स्थापित करेंगें | RBI द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक 22.02.2021 को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक प्रस्तावित है |

उन्होंने जिला स्तर पर होने वाले DCC बैठक के सम्बन्ध में कहा कि SLBC द्वारा आगामी सभी चारों तिमाही हेतु DCC की बैठक का कैलेन्डर तैयार कर सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों के Circulate किया जाना चाहिए | सभी अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि उनके जिले में DCC मीटिंग तय कैलेन्डर के हिसाब से हो | उन्होंने साथ ही सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार से अनुरोध किया कि इस सम्बन्ध में अपने सभी जिलों के जिला उपायुक्त को भी अवगत कराएँ |

**(एक्शन- सभी एलडीएम/ राज्य सरकार )**

उन्होंने SLBC को reporting के लिए Automated Data Flow system के सम्बन्ध में कहा कि अभी भी कुछ बैंकों द्वारा इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है | उन्होंने जानकारी दी कि यह प्रोजेक्ट मार्च, 2021 से पहले लागू किया जाना है एवं इसके लिए RBI द्वारा जल्दी ही एक रिव्यु मीटिंग किया जायेगा |

**(एक्शन- सभी बैंक/एसएलबीसी )**

राज्य में BC/CSP आउटलेट द्वारा गलत कार्यप्रणाली अपनाने, जैसे - ज्यादा चार्ज लेना, आबंटित जगह पर कार्य नहीं करना आदि सम्बंधित शिकायतों के सम्बन्ध में कहा कि सभी बैंक नियंत्रकों द्वारा यह सुनिश्चित करें कि उनके सभी BC/CSP आउटलेट सही तरीकें से RBI एवं बैंक के नियमानुसार कार्य कर रहे हैं |

**(एक्शन- सभी बैंक/एसएलबीसी )**

राज्य का पूर्वी सिंहभुम जिला, जिसे 31 मार्च, 2021 तक 100% डिजिटल जिला बनाने का लक्ष्य निर्धारित है, के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि वर्तमान में Individual accounts के मामले में 85% एवं Business खातों के मामले में 67% उपलब्धि रही है | उन्होंने कहा कि इसकी रिव्यु के लिए RBI द्वारा 17 फ़रवरी ,2021 को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग प्रस्तावित किया गया है |

**(एक्शन- सभी बैंक/एसएलबीसी )**

उन्होंने आगे कहा कि Last SLBC मीटिंग के दौरान सभी RSETIs को एक साझा वेबसाइट सृजित किया जाना चाहिए, जिसमें सभी RSETIs को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा लंबित क्रेडिट लिंकेज आवेदन की जानकारी उपलब्ध हो | SLBC द्वारा इस प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए तथा इसका Login Credentials सभी RSETIs निदेशक को देकर उपरोक्त जानकारी अपडेट किया जाना चाहिए |

**(एक्शन- एसएलबीसी )**

अंत में उन्होंने SLBC को दिनांक 26.03.2021 को राज्य में Financial Inclusion and Literacy की स्थिति की समीक्षा हेतु विशेष SLBC मीटिंग करने का अनुरोध किया | इस मीटिंग में भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के उच्च अधिकारी शामिल होंगे | उन्होंने SLBC को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाना चाहिए | उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स को इस बैठक हेतु वांछित डाटा SLBC को तुरन्त उपलब्ध कराने को कहा |

**( एक्शन- सभी बैंक/एसएलबीसी )**

इस सम्बोधन के पश्चात के श्रीमती हिमानी पाण्डेय, सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखंड सरकार को सभा को संबोधित करने का आग्रह किया गया। उन्होने सर्वप्रथम जानकारी दी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में होने वाली विशेष SLBC कुछ कारणों से नहीं हो पाई |

उन्होंने दिसम्बर, 2020 तिमाही का डाटा में कृषि क्षेत्र की उपलब्धि अच्छी नहीं है | उन्होंने कहा कि राज्य के दो प्रमुख बैंक भारतीय स्टेट बैंक एवं बैंक ऑफ़ इंडिया की ACP उपलब्धि क्रमशः 13%एवं 33.32% रही, राज्य में उनके उपस्थिति की तुलना में काफी निराशाजनक है |

**(एक्शन- भारतीय स्टेट बैंक/BOI)**

उन्होंने आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत एवं KCC Saturation Dirve under डेयरी-फिशरी एक्टिविटी तथा PM किसान के क्षेत्र में बैंकों को और अधिक कार्य करने की जरुरत है | इस सम्बन्ध में, बैंकों से नियमित रिव्यु मीटिंग की जा रही है, किन्तु इसमें उतनी प्रगति नहीं हो पाई है |

**(एक्शन- सभी बैंक/एलडीएम)**

उन्होंने शिक्षा ऋण के मामले में कहा कि राज्य में बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7,625 छात्रों को शिक्षा ऋण स्वीकृत किया गया, जिनमें से अनुसूचित जाति व जनजाति (SC/ST) के केवल 413 छात्रों को ही शिक्षा ऋण स्वीकृत किया गया | यह झारखण्ड जैसे राज्य के लिए अत्यंत चिंतनीय है | सभी स्टेक होल्डर्स को इस मामले पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है |

**(एक्शन- सभी बैंक/एलडीएम)**

उन्होंने आगे कहा कि झारखण्ड द्वारा दिसम्बर तिमाही में ACP उपलब्धि, हमारे पड़ोसी राज्य छतीसगढ़ द्वारा प्रथम तिमाही के ACP उपलब्धि के बराबर है, जबकि लॉकडाउन का प्रभाव पुरे देश में एक सामान था | राज्य में मुख्य फसल खरीफ की होती है, जिसमें कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण में वृद्धि प्रथम तिमाही में होनी चाहिए |

**(एक्शन- सभी बैंक/एलडीएम)**

इस सम्बोधन के पश्चात के श्री अबूबकर सिद्दीकी, सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार को सभा को संबोधित करने का आग्रह किया गया।

उन्होंने कहा कि SLBC द्वारा दर्शाए गए दिसम्बर, 20 तिमाही में कुल KCC की संख्या दिसम्बर,19 की तुलना में घटकर 13.72 लाख रह गया, जबकि राज्य में कुल पीएम किसान के लाभुकों की संख्या 31.85 लाख है | अतः राज्य में कम से कम 31.85 लाख KCC खाते होने चाहिए | उन्होंने राज्य में चल रहे KCC Saturation Drive under Dairy-Fishery Activity के सम्बन्ध में कहा कि डेयरी एवं फिशरी विभागों द्वारा बैंकों को भेजे गए आवेदनों की तुलना में स्वीकृत आवेदनों की संख्या बहुत कम है | उन्होंने कहा कि डेयरी विभाग द्वारा लगभग 33,000 आवेदन बैंकों को भेजें गए हैं, जबकि बैंकों ने केवल 21,383 आवेदन प्राप्त होने की सुचना दी है, जिनमें से केवल 4,749 स्वीकृत किया गया है तथा 10,000 से अधिक आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है | इसीप्रकार, फिशरी के मामले में भी विभाग द्वारा 19,032 आवेदन बैंकों को भेजें गएँ, जबकि बैंकों द्वारा 11,874 आवेदन ही प्राप्त होने की सूचना दी गई है, जिनमें से केवल 1,264 ऋण आवेदन स्वीकृत किये गए हैं तथा 8,419 आवेदन रिजेक्ट किया गया है | उन्होंने कहा कि डेयरी एवं फिशरी

विभाग द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद भी बैंकों द्वारा ऋण आवेदनों को रिजेक्ट किया जाना बहुत निराशाजनक है | SLBC को इस मामले को गंभीरता के लेने की जरुरत है | उन्होंने जिलास्तर पर सभी स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित कर बैंकों को प्राप्त नहीं हुए आवेदनों की जाँच करनी चाहिए |

**(एक्शन- सभी बैंक/एलडीएम/एसएलबीसी)**

उन्होंने आगे कहा कि राज्य में जिला उपायुक्त द्वारा जाँच के उपरांत ही लाभुक का डाटा PM किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाता है तथा वे लाभुक को किसान के रूप में प्रमाणिक भी करते हैं| अतः बैंकों को उन्हें KCC देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए एवं उन्हें PM किसान लाभुकों से लैंड रिकॉर्ड भी लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए |

**(एक्शन- सभी बैंक/एलडीएम/एसएलबीसी)**

उन्होंने झारखण्ड सरकार की अतिमहत्वकांक्षी योजना झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में कृषि ऋण माफ़ी हेतु लगभग 11 लाख योग्य KCC फार्मर्स हैं | सरकार द्वारा ऋण माफ़ी हेतु इस वित्तीय वर्ष में 2,000 करोड़ का Provision किया गया है | उन्होंने कहा कि अभी तक बैंकों द्वारा केवल 2 लाख डाटा ही पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जबकि अभी भी 9 लाख डाटा अपलोड किया जाना शेष है | उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे अपने सभी योग्य KCC खाताओं का डाटा यथाशीघ्र पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे राज्य के किसानों को इसका लाभ तुरंत मिल सके और बैंक इस बात का ध्यान रखे कि राज्य का कोई भी योग्य किसान इस योजना के लाभ से वंचित न हो |

**(एक्शन- सभी बैंक/एलडीएम)**

उन्होंने आगे कहा कि एग्री इन्फ्रा फंड में राज्य का लक्ष्य 300 प्रोजेक्ट्स का निर्धारित था, किन्तु अभी तक की उपलब्धि शून्य है | उन्होंने कहा कि पिछली SLBC की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि सभी जिलों में कम से कम एक प्रोजेक्ट बैंकों द्वारा इस योजना में फाइनेंस किया जाना है, किन्तु अभी तक परिणाम शुन्य है | उन्होंने दुबारा बैंकों से अनुरोध किया कि सभी बैंकें 31 मार्च 2021 तक प्रत्येक ज़िले मे कम से कम एक प्रोजेक्ट जरुर फाइनेंस करें |

**(एक्शन- सभी बैंक/एलडीएम)**

इस सम्बोधन के पश्चात के श्रीमती आराधना पटनायक, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार को सभा को संबोधित करने का आग्रह किया गया।

उन्होने DAY NRLM के अंतर्गत एसएचजी क्रेडिट लिंकेज की कुल उपलब्धि पोर्टल के अनुसार दिसम्बर,2020 तक 84% की है, जबकि वितरण की उपलब्धि 83% है | उन्होंने आगे कहा कि लगभग 25,000 आवेदन राज्य के विभिन्न बैंकों के पर अभी भी लंबित पड़े हैं | उन्होंने कहा कि SLBC की सब-कमेटी की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि फ़रवरी, 2021 के अंत तक बैंकों द्वारा सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन कर लिया जायेगा | उन्होंने इसी क्रम में आगे कहा कि राज्य में बैंकों द्वारा एसएचजी

क्रेडिट लिंकेज में बैंकों द्वारा औसत Drawing Power रु. 75,000 दिया जा रहा है, जबकि एसएचजी क्रेडिट लिंकेज में देश के औसत Drawing Power रु.1,25,000 है | अतः उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि सभी एमएचजी क्रेडिट लिंकेज खातों में प्रथम वर्ष में कम से कम एक लाख का Drawing Power जरुर दें | अभी भी झारखण्ड में 75% एसएचजी क्रेडिट लिंकेज खातों में Drawing Power एक लाख से कम है | उन्होंने आगे कहा कि राज्य में एसएचजी क्रेडिट लिंकेज खातों का NPA बहुत कम (लगभग 3% ) है | अतः बैंकों को SHG क्रेडिट लिंकेज में परेशानी नहीं होनी चाहिए |

उन्होंने कहा कि राज्य में अभी 2.50 लाख SHG का गठन किया जा चूका है, जिसमें से 2.34 लाख SHG का बचत खाता खोले जा चुकें हैं, जबकि 1.44 लाख SHG का क्रेडिट लिंकेज किया जा चूका है | उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि शेष बचे 90,000 SHG खातों का क्रेडिट लिंकेज करने में सहयोग करें |

इसके अतिरिक्त उन्होने एसएचजी की महिलाओं को विभिन्न बैंकों में बैंकिंग सखी के रूप नियुक्त करने हेतु प्राथमिकता देने की बात कही | उन्होने राज्य सरकार द्वारा एक-पंचायत एक-बैंकिंग सखी नियुक्त करने एवं उसके पंचायत भवन में कार्य करने की योजना की जानकारी दिया तथा सभी बैंकों के Controlling Heads से अनुरोध किया कि वे अपनी शाखाओं को इस दिशा में कार्य करने हेतु निर्देशित करें | इसके अतर्गत उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में राज्य के 3000 बड़े पंचायतों में बैंकिंग सखी नियुक्त करने की योजना है, जिनमें से अभी 1000 पंचायतों में बैंकिंग सखी नियुक्त किया जा चुका है, शेष 2000 पंचायतों में बैंकों के माध्यम से बैंकिंग सखी नियुक्त किया जाना है ।

**(एक्शन- सभी बैंक/एलडीएम/जेएसएलपीएस)**

श्रीमती पटनायक महोदया द्वारा RSETI भवन के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुये बताया कि अभी 10 RSETI भवन का कार्य प्रगति में है जिसमे एसबीआई के 7, इंडियन बैंक के 2 एवं बैंक ऑफ इंडिया का 1 है | उन्होंने SBI द्वारा संचालित RSETI भवन निर्माण की धीमी प्रगति पर चिंता प्रकट किया तथा अनुरोध किया कि SBI से इसमें तेजी लाने का अनुरोध किया | उन्होने रामगढ़ RSETI के संबंध में जानकारी दी कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा भवन निर्माण हेतु आबंटित राशि बैंक ऑफ इंडिया को हस्तांतरण हेतु आदेश जारी किया गया है एवं राज्य सरकार द्वारा भूमि का आबंटन भी किया जा चुका है | अत: बैंक ऑफ इंडिया से अनुरोध किया गया कि रामगढ़ RSETI का निर्माण कार्य प्रारम्भ करें | उन्होने लोहरदगा RSETI का निर्माण कार्य दुबारा शुरू करने के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया से अनुरोध किया |

**(एक्शन- बीओआई/एसबीआई/इंडियन बैंक)**

इस सम्बोधन के पश्चात के डा॰ मदनेश मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार को सभा को संबोधित करने का आग्रह किया गया। उन्होने सर्वप्रथम एसएलबीसी की बैठक में राज्य सरकार से विकास आयुक्त के उपस्थिति पर ख़ुशी जाहिर की |साथ ही साथ विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों की उपस्थिति पर कहा कि यह SLBC फोरम को सार्थक बनाता है |

उन्होंने आगे कहा कि RBI द्वारा जारी लीड बैंक स्कीम के गाइडलाइन्स के अनुसार यदि SLBC की मीटिंग में शामिल विशेष प्रतिनिधियों द्वारा सभा का संबोधन जरुरी नहीं है, तो हमें सीधे एजेंडा एवं Action Taken Report पर चर्चा करनी चाहिए एवं इसी दौरान प्रतिनिधि अपने सुझाव एवं समस्या रखें | ऐसा नहीं होने पर SLBC फोरम में शामिल प्रतिनिधियों द्वारा स्पीच देने के बाद मुद्दें वही समाप्त हो जाते है | इसलिए सीधे एजेंडा पर चर्चा करने से यह काफी लाभदायक होगा | उन्होंने सुझाव दिया कि अगली बार से SLBC की मीटिंग में केवल एजेंडा एवं ATR पर चर्चा की जानी चाहिए | उदाहरण के लिए कि उन्होने कहा कि ATR में यह दर्शाया गया है कि प्राइवेट बैंक द्वारा SLBC को डाटा नहीं दिया जा रहा है,तो इसमें सम्बंधित बैंक का नाम दिया जाना चाहिए | सभी प्राइवेट सेक्टर बैंकों को सरकार द्वारा प्रायोजित योजनायों में सहयोग करना है और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो इसकी सुचना SLBC फोरम के माध्यम से सरकार तक पहुँचानी चाहिए |

**(एक्शन- सभी बैंक/एलडीएम)**

उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष के बजट में बैंक-ग्राहकों के लिए Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation (DICGC) के अंतर्गत कवरेज एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है | इससे बैंक में जमा ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा | उन्होंने जानकारी दी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नया पेंशन व्यवस्था ला रही है | PFRDA के साथ इस सम्बन्ध में चर्चा चल रही है | सरकार बहुत जल्दी ही इसपर कोई निर्णय ले सकती है |

**(एक्शन- सभी बैंक/एलडीएम)**

उन्होंने e-स्टम्पिंग के सम्बन्ध में कहा कि सरकार पुरे देश में यह व्यवस्था लागु करना चाहती है | PSB सहित सभी बैंक एवं झारखण्ड सहित कई राज्य इसके लिए तैयार हैं एवं सरकार इसको इसी वर्ष अप्रैल महीने से पुरे देश में लागु करना चाहती है | इससे बैंकों को अपने डाक्यूमेंट्स की स्टम्पिंग में काफी सहूलियत होगी |

**(एक्शन- सभी बैंक/एलडीएम)**

उन्होंने कहा कि भारत सरकार बैंकों के माध्यम से चलाये जा रहे वैसे क्रेडिट लिंक स्कीम, जिनमें सरकार सब्सिडी या Interest Subvention देती है, के लिए एक कॉमन पोर्टल तैयार कर रही है एवं जल्दी ही यह शुरू किया जा सकता है | शुरुआत में इसमें 16 क्रेडिट लिंक स्कीम को शामिल किया जा रहा है | सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों से बैंकिंग क्षेत्र में काफी परिवर्तन होगा|

उन्होंने आगे शिक्षा ऋण के सम्बन्ध में कहा कि झारखण्ड राज्य एजुकेशनल हब है | यहाँ के छात्र शिक्षा के लिए देश-विदेश जाते है, किन्तु फिर भी राज्य में शिक्षा ऋण उतना नहीं है | राज्य में अच्छी खासी SC/ST आबादी होने पर भी शिक्षा ऋण में SC/ST छात्रों की संख्या निराशाजनक है | उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि अगले कुछ महीनों में Technical एवं Managment कालेजों में प्रवेश शुरू होंगे और बैंक कैम्प लगाकर ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लोन दें, जिससे झारखण्ड के छात्रों विशेषकर SC/ST गरीब छात्रों को लाभ मिल सके | सरकार द्वारा 7.50 लाख तक के शिक्षा ऋण में CGFSEL के तहत गारंटी कवर दिया जाता है |

**(एक्शन- सभी बैंक/एलडीएम)**

उन्होंने राज्य में पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति के सम्बन्ध में कहा कि बैंकों को इसमें और अधिक काम करने की जरुरत है | उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य का उदहारण दिया, जहाँ इस योजना में एक लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया गया है | स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रु.10,000 की राशि बहुत अधिक होती है एवं यह लॉक डाउन के बाद उन्हें दुबारा अपने व्यवसाय को शुरू करने में काफी मदद करेगा | यह प्रधानमंत्री की अतिमहत्वकांक्षी योजना है | उन्होंने राज्य सरकार से भी अनुरोध किया कि इस योजना का प्रचार-प्रसार करते हुए सभी स्ट्रीट वेंडर्स को उनके लिए चलाये जा रहे इस योजना की जानकारी दें तथा उनके आवेदन को बैंकों तक पहुंचाए | उन्होंने जिला उपायुक्त को भी सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से चलायी जा रही योजनायों की अपने जिले में पूरा प्रचार-प्रसार करें एवं समय-समय पर इसकी समीक्षा भी करें | उन्होंने राज्य स्तर पर समीक्षा के लिए विकास आयुक्त के भी अनुरोध किया | उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के लिए कहा कि वे राज्य में SBI बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक महाप्रबंधक की नियुक्ति के लिए उनके चेयरमैन से बात की है | यह राज्य एवं SBI दोनों की छवि में परिवर्तन के लिए जरुरी है |

**(एक्शन- सभी बैंक/एलडीएम)**

उन्होंने कहा कि यदि सरकार द्वारा 10,000 ऋण आवेदन सृजित कर बैंकों के भेजा जाता है, तो उनमें से केवल 3,000 ऋण आवेदन ही बैंकों द्वारा स्वीकृत किया जाता है | इस विषय में सरकार एवं बैंकों को एक साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि बैंक को ऋण आवेदन के साथ किस प्रकार की जानकारी एवं डॉक्यूमेंट चाहिए तथा सरकार का उद्देश्य क्या है ? इससे सरकार एवं बैंक के बीच की दूरी कम होती है | उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने विभाग द्वारा तैयार PSB Loan in 59 Minutes के पोर्टल निर्माण का अनुभव साझा किया | उन्होंने कहा कि सभी बैंकों से चर्चा के बाद ही पोर्टल का निर्माण किया गया और वर्तमान में, इस पोर्टल के माध्यम से कई प्रकार के ऋण जैसे, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन आदि के आवेदन बैंकों को प्रेषित एवं प्रोसेस किये जाते हैं | उन्होंने बैंकों में Fintech की उपयोगिता की चर्चा करते हुए कहा कि अब बैंकों को मार्किट डिमांड के आधार पर प्रोडक्ट तैयार करना चाहिए | उन्होंने कहा कि सरकार MSME में फाइनेंस के लिए नई गाइडलाइन्स जारी करने पर विचार कर रही है | नये गाइडलाइन्स में NBFCs को भी MSME फिनानंस की अनुमति मिलेगी | इससे MSME यूनिट्स को फायदा होगा |

**(एक्शन- सभी बैंक/एलडीएम)**

उन्होंने आगे कहा कि Covid महामारी के दौरान बैंकों द्वारा सरहनीय कार्य किया गया | लॉकडाउन के समय सरकार द्वारा महिलायों के खाते में जमा किये गए रु.500 को बैंकों के माध्यम से करने में सामजिक दुरी का ध्यान रखते हुए भुगतान कार्य किया गया, जोकि बैंक कर्मियों की मेहनत को दर्शाता है | डेयरी एवं फिशरी को KCC देने के मामले में बैंकों द्वारा पशु बीमा करने से सम्बन्धित परेशानी को देखते हुए उन्होंने सलाह दी कि SLBC के बैठक में General Insurance Co. के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित करें |

**(एक्शन- सभी बैंक/एसएलबीसी)**

अंत में, उन्होंने SLBC की बैठक में शामिल होने के लिए राज्य के विकास आयुक्त, प्रधान सचिव, RBI, नाबार्ड एवं बैंकों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया |

एसएलबीसी की 74वी त्रैमासिक बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

**(राजेंद्र मान पाण्डेय)**

**महाप्रबंधक,रा. स्त. बै. स.**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखण्ड